



ओडिशा मार्च 2026 तक माओवाद से मुक्त होगा: पुलिस का दावा



भुवनेश्वर, 26 दिसंबर 2025: ओडिशा पुलिस ने कहा है कि मार्च 2026 तक राज्य को माओवादी गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक वाई. बी. खुरानिया ने बताया कि राज्य में माओवादी आत्मसमर्पण नीति सफल रही है और हिंसा छोड़ने वाले माओवादी मुख्यधारा में लौट सकते हैं।

खुरानिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी माओवादी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। अब तक अभियान में माओवादी नेटवर्क कमजोर हुआ है और पुलिस सभी क्षेत्रों में सतर्क है। माओवादियों से अपील की गई है कि वे हिंसा छोड़कर समाज में शामिल हों, ताकि ओडिशा जल्द नक्सल-मुक्त बन सके।



ग्रामीण रोजगार गारंटी में 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' केवल इन महिलाओं को मिलेगा - जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली, : सरकार ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ करने का नया तरीका अपनाया है। मन्रेगा (MGNREGA) के स्थान पर अब 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G कानून लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सालाना 125 दिन रोजगार गारंटी देना है।

जिसके आधार पर ही ग्रामीण मजदूरों को काम मिलेगा। विशेष रूप से एकल महिलाओं (single women) को विशेष प्रकार का रोजगार गारंटी कार्ड दिया जाएगा ताकि उन्हें प्राथमिकता के साथ काम और लाभ मिल सके। इसके अलावा दिव्यांग, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक और कुछ जनजाति वर्ग के लोग भी इससे जुड़ पाएंगे।

इस नए प्रावधान के तहत अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा, केन्द्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से महिलाओं और कमजोर वर्गों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी। योजना के तहत जल संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और सतत विकास जैसे कार्यों पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इस प्रकार, विशेष रूप से एकल महिलाओं के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में प्रथमिकता सुनिश्चित की गई है, ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें।

सीईटी 2026 के लिए आधार व APAAR ID अनिवार्य, अपंग अभ्यर्थियों को UDID कार्ड भी जरूरी

मुंबई, 25 दिसंबर 2025: महाराष्ट्र राज्य सीईटी 2026 के लिए अब आधार प्रमाणीकरण और APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सीईटी कक्ष के अनुसार, सीईटी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों को मान्य आधार कार्ड और APAAR ID आवेदन के समय दर्ज करना होगा, नहीं तो वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड में उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, पता तथा आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है।

विशेष रूप से अपंग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। यदि UDID (Unique Disability ID) कार्ड उपलब्ध है तो उसे आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकरण का अपंगत्व प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है। सीईटी कक्ष ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते सभी दस्तावेज तैयार और अपडेट करके रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए। आधिकारिक अधिसूचना और आगामी परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए सीईटी कक्ष की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विज़िट करने की सलाह दी गई है।

WORLD NEWS | बांग्लादेश में गैर-मुसलमानों पर हो रहा अकल्पनीय अत्याचार, बांग्लादेश में गैर-मुसलमानों पर हो रहा अकल्पनीय अत्याचार, शेख हसीना ने मोहम्मद युनूस सरकार पर किया सीधा वार



नई दिल्ली | बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बृहस्पतिवार को जमकर हमला बोला और उस पर गैर-मुसलमानों के खिलाफ 'अकल्पनीय अत्याचार' करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख 78 वर्षीय हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली युनूस सरकार में "धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं।" उनका इशारा स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में पिछले हफ्ते एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना की ओर था।

गैर-मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में युनूस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के अपने-अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार खासतौर पर गैर-मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रही है। उसके शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं भी सामने आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश की जनता इस काले दौर को और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी। "



लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा, 7 आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता | लखनऊ, : उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) में बड़े पैमाने पर फर्जी लाभार्थी कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

STF के मुताबिक आरोपी संगठित तरीके से **विभिन्न जिलों में करीब **2,000 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए, जिनका इस्तेमाल पात्रता नहीं रखने वाले व्यक्तियों को सरकारी स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए किया गया। ऐसा करने के लिए उन्होंने OTP वेरिफिकेशन को बायपास किया और नकली पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया।

पुलिस ने गोमतीनगर एक्सटेंशन इलाके से गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, कंप्यूटर, नकली दस्तावेज और अन्य डिजिटल सामग्री भी जब्त की है। STF की पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने प्रत्येक नकली कार्ड के लिए लाखों रुपये कमाए और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया। आरोपियों पर संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई और विस्तृत जांच जारी है, जिसमें अन्य संभावित आरोपियों की पहचान करने पर भी काम चल रहा है।

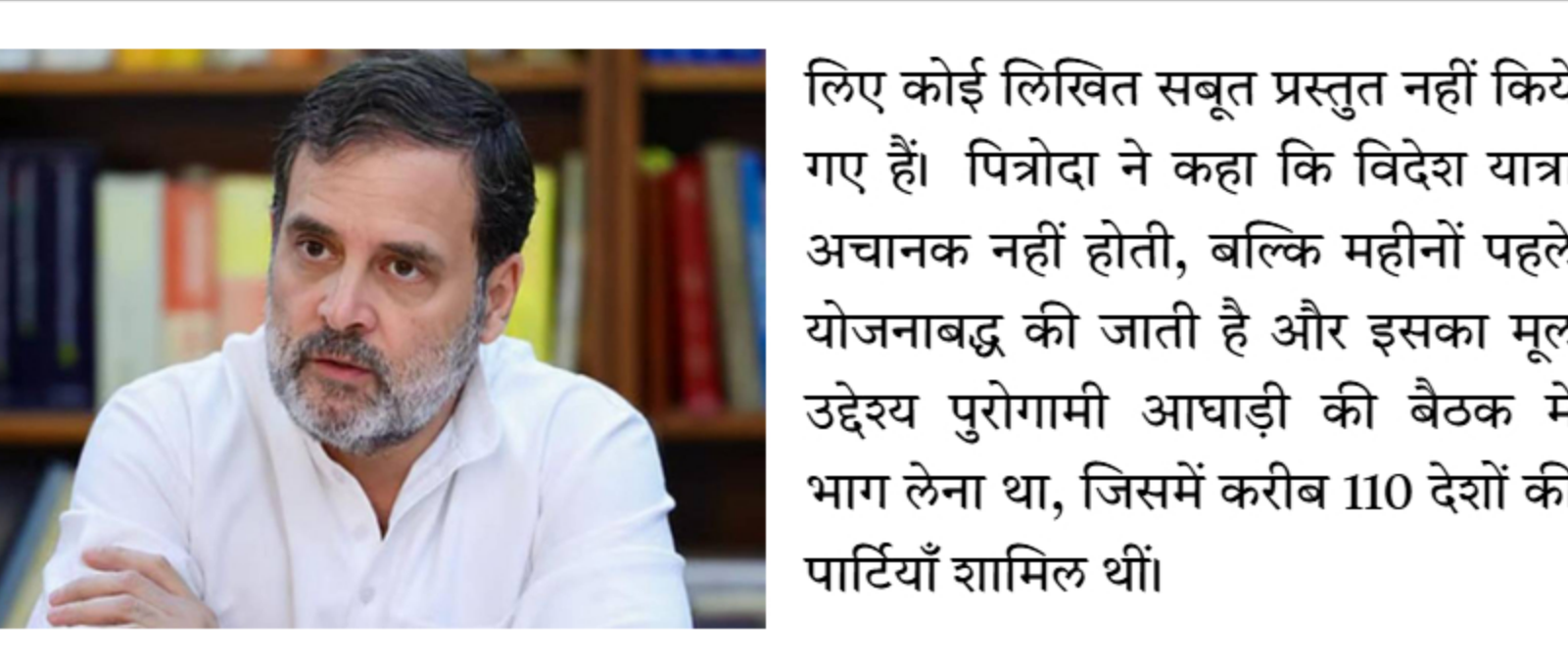


लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, पीएम मोदी का अनुच्छेद 370 और 'परिवारवाद' पर निशाना

लखनऊ, 25 दिसंबर 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया। यह स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65-फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं और आधुनिक म्यूजियम के साथ देशभक्ति व नेतृत्व की कहानी दर्शाता है। समावेशी विकास पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब देश की प्रगति का श्रेय केवल एक परिवार से जोड़ने का दौर गया और भाजपा सरकार को गर्व है कि उसने अनुच्छेद 370 को 'दीवार' गिराने का मौका पाया, जिससे जम्मू-कश्मीर में संविधान की पूर्ण रूप से लागू होने की दिशा में कदम बढ़ा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और

कांग्रेस का दावा: राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर केंद्र सरकार द्वारा निगरानी, गंभीर आरोप लगे



नई दिल्ली, : इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने **केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी की विदेशी दौड़ों के दौरान निगरानी और पाळत रखी जाती है। पित्रोदा ने यह आरोप विशेष रूप से राहुल गांधी के हालिया जर्मनी दौर के संदर्भ में लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के अधिकारी उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे थे।

एक मीडिया इंटरव्यू में पित्रोदा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के होटल से लेकर बैठक स्थानों तक और यहां तक कि हवाईअड्डों पर भी उनका पीछा किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई बार विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से हतोत्साहित किया गया, हालांकि इसके

लिए कोई लिखित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। पित्रोदा ने कहा कि विदेश यात्रा अचानक नहीं होती, बल्कि महीनों पहले योजनाबद्ध की जाती है और इसका मूल उद्देश्य पुरोगामी आघाड़ी की बैठक में भाग लेना था, जिसमें करीब 110 देशों की पार्टियाँ शामिल थीं।

उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष द्वारा ऐसे आरोप लगाया जाता है जैसे कि राहुल गांधी विदेश में "भारत विरोधी बयान" दे रहे हैं, लेकिन पित्रोदा ने इन आरोपों को "बकवास" करार दिया और कहा कि राहुल या कांग्रेस का किसी भी तरह की विदेशी फंडिंग या 'एंटी-इंडिया नेटवर्क' से कोई लेना-देना नहीं है।

पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस देश के भीतर और विदेशों में लोकतंत्र, संस्थानों की स्वतंत्रता और विचारों के आदान-प्रदान के लिए खुलकर बात करेगी, चाहे किसी भी मंच पर हो। इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा और प्रतिक्रियाएँ तेज़ हो रही हैं।

प्रशांत जगताप ने 27 साल बाद NCP (शरद पवार) से इस्तीफा दिया, सुप्रिया सुळे ने दी 'नई सुबह' की प्रतिक्रिया

पुणे/मुंबई, 25 दिसंबर 2025: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के पुणे शहराध्यक्ष और पूर्व महापौर प्रशांत जगताप ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और शहराध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह कदम पुणे महापालिका चुनाव से पहले दोनों NCP गुटों के संभावित गठजोड़ के विरोध में उठाया। जगताप का कहना रहा कि वे पार्टी के कुछ नीतिगत फैसलों और गठबंधन की दिशा से असहमत थे, इसलिए उन्होंने 27 साल की जुड़ाव के बाद यह निर्णय लिया। वे चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की भी योजना बना रहे हैं।

जगताप ने मीडिया से कहा कि पार्टी के भीतर चुनाव रणनीति और गठबंधन को लेकर स्पष्टता का अभाव रहा है, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति से बाहर नहीं जा रहे और आगामी निगम चुनावों में भाग लेने का इरादा रखते हैं।

इस घटनाक्रम पर पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुळे ने कहा, "रोज नई सुबह होती है...", यह दर्शाता है कि राजनीतिक बदलाव और चुनौतियाँ स्वाभाविक हैं। उन्होंने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के हित और विचारों को प्राथमिकता देने हुए गठबंधन पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। सुळे ने यह भी भरोसा दिलाया कि शरद पवार के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी।

जगताप के इस्तीफे ने स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है और अब देखना यह है कि वे किस राजनीतिक मोर्चे से आगे उतरते हैं तथा NCP के दोनों गुट आगामी चुनावों में अपना रणनीतिक कैसे बनाते हैं।

SIR 2025 : सुधार की प्रक्रिया या मताधिकार की अग्रिपरीक्षा?

संपादकीय...।

देश में मतदाता सूची की शुद्धता के उद्देश्य से चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया आज केवल एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं रह गई है, बल्कि यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा अहम प्रश्न बन चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का दावा है कि SIR का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य नामों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है। लेकिन 25 दिसंबर 2025 तक सामने आए सरकारी आंकड़े और मीडिया रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि यह प्रक्रिया जितनी आवश्यक है, उतनी ही संवेदनशील भी।

चुनाव आयोग और भारत सरकार के अनुसार, SIR 2025 के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार शामिल हैं। Moneycontrol, Business Standard और LiveMint जैसी प्रतिष्ठित समाचार संस्थाओं की रिपोर्टों के मुताबिक, इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब साढ़े तीन करोड़ नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं।

राज्यवार आंकड़े इस प्रक्रिया की व्यापकता को और स्पष्ट करते हैं। Times of India के अनुसार, तमिलनाडु में लगभग एक करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए, जिनमें मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल बताए गए। पश्चिम बंगाल में करीब छह करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची में संशोधन हुआ, जिसमें से लगभग 58 लाख नाम हटाए गए। मध्य प्रदेश में करीब 40 से 45 लाख, केरल में लगभग 24 लाख, छत्तीसगढ़ में करीब 27 लाख और गुजरात में सात करोड़ से अधिक प्रविष्टियों में संशोधन या डिलीशन की बात सामने आई है।

चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्ट है। ECI का कहना है कि ये सभी हटाए गए नाम ड्राफ्ट स्तर पर हैं और अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए दावा-आपत्ति (Claims & Objections) की पूरी व्यवस्था मौजूद है। आयोग ने हेल्पलाइन 1950, NVSP पोर्टल और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से शिकायत निवारण की सुविधा भी दी है। सरकार का यह भी दावा है कि किसी भी योग्य नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

लेकिन लोकतंत्र केवल आश्वासनों से नहीं चलता, अनुभव से चलता है। जमीनी स्तर पर सामने आ रही शिकायतें यह बताती हैं कि बड़ी संख्या में नागरिक—विशेषकर बुजुर्ग, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण मतदाता और शहरी गरीब—इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम और असमंजस में हैं। कई मामलों में बिना स्पष्ट सूचना के नाम हटने की शिकायतें मीडिया में दर्ज हुई हैं। यही कारण है कि SIR को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी तीखी बहस देखने को मिल रही है।

यह स्वीकार करना होगा कि फर्जी मतदान और डुप्लीकेट मतदाता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। मतदाता सूची की सफाई आवश्यक है। लेकिन उतना ही बड़ा खतरा यह है कि एक भी वास्तविक मतदाता गलती से सूची से बाहर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएँ और अदालत द्वारा समयसीमा व प्रक्रिया में संवेदनशीलता बरतने की सलाह यह दर्शाती है कि मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवैधानिक महत्व का भी है।

लोकतंत्र में एक सिद्धांत हमेशा याद रखा जाना चाहिए—निष्पक्षता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसका दिखाई देना भी है। जब एक साथ करोड़ों नाम हटाए जाते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल आंकड़े सुधारने की नहीं, बल्कि नागरिकों का भरोसा बनाए रखने की भी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि SIR को जल्दबाजी के बजाय पारदर्शिता, आदेश के बजाय संवाद और कठोरता के बजाय मानवीय दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए। राजनीतिक दलों को भी इसे केवल आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बनाने के बजाय मतदाताओं को सही जानकारी देने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

आखिरकार, लोकतंत्र की असली ताकत मतदाता है। यदि सुधार की प्रक्रिया में वही खुद को असुरक्षित या उपेक्षित महसूस करने लगे, तो सुधार का उद्देश्य ही सवाल के घेरे में आ जाता है। SIR की सफलता का पैमाना आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि यह होगा कि अंतिम मतदाता सूची में कोई भी पात्र नागरिक खुद को बाहर खड़ा न पाए। यदि सुधार के नाम पर भरोसा कमजोर पड़ा, तो उसका नुकसान किसी एक सरकार या दल को नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा।

WORLD NEWS | चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक,

चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, पाकिस्तान प्रमुख खरीदार: पेंटागन रिपोर्ट

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीनी सेना से जुड़ी नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चीनी हथियारों के बढ़ते व्यापार, पाकिस्तान के साथ इसके मजबूत होते रक्षा संबंधों पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि चीन अपने हथियारों की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों का उत्तर देने के लिए वित्तीय मदद दे रहा है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी युद्ध विभाग ने चीनी सेना से जुड़ी 2025 की नई रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। इसमें लिखा है कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। पाकिस्तान, चीन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा रक्षा खरीदार बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक चीन ने दुनियाभर के देशों को बड़ी संख्या में हथियार बेचे हैं।



इनमें सबसे ज्यादा छोटे हथियार हैं, जो तीसरी दुनिया के देशों को दिए गए हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को हवा, जमीन और समुद्र में मार करने वाले हथियारों और उपकरणों का निर्यात जारी रखा है। चीन ने पाकिस्तान को कौन से हथियार बेचे रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 36 J-10C मल्टीरोल फाइटर जेट

दिए हैं। इसके साथ पाकिस्तान, चीन से यह लड़ाकू विमान पाने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। इसके अलावा चीन ने 2017 और 2018 के बीच पाकिस्तान को चार नौसैनिक फ्रिगेट की आपूर्ति की है। इनके अलावा चीन ने पाकिस्तान को कैहोंग और विंग लुंग जैसे मिलिट्री ड्रोन भी सौंपे हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और

तकनीकी सहयोग को रेखांकित करता है। चीन किन देशों को बेच रहा हथियार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन वर्तमान में निर्यात के लिए तीन लड़ाकू विमान पेश करता है, जिसमें पांचवीं पीढ़ी का FC-31, चौथी पीढ़ी का J-10C, और चीन-पाकिस्तान का संयुक्त रूप से निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान शामिल है।

ड्रोन अलावा चीन ने पाकिस्तान, अल्जीरिया, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक, मोरक्को, म्यांमार, सर्बिया और यूएई सहित कई देशों को हमलावर सैन्य ड्रोन की डिलीवरी की है।

चीनी हथियारों की बिक्री पर जताई गई चिंता पेंटागन की रिपोर्ट में एशिया और अफ्रीका में चीनी हथियारों की बढ़ती बिक्री पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि कई विकासशील देश पश्चिम के महंगे हथियारों की तुलना में कम लागत के कारण चीन से हथियार खरीद रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "कई विकासशील देश, विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप के, चीन की हथियार खरीदते हैं क्योंकि वे पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीली हैं।" इसमें कहा गया है कि चीन अपने हथियारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित आशंकाओं को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराता है।

बांग्लादेश में एक और हिंदू की पीट-पीटकर हत्या, कट्टरपंथियों की भीड़ ने ले ली सम्राट मंडल की जान

बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अमृत मंडल उर्फ सम्राट नामक यह व्यक्ति एक आपराधिक गिरोह का सरगना था। वह जबरन वसूली के लिए एक ग्रामीण के घर गया था। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

ढाका: बांग्लादेश में एक और हिंदू आदमी को पीट-पीटकर मार डाला गया है। इसके कुछ ही दिन पहले दीपू चंद्र दास की भी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। कट्टरपंथियों ने दीपू के शव को जला दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट की राजबाड़ी के पांगशा सब-डिवीजन में रात करीब 11 बजे हत्या कर दी गई। यह जगह राजधानी ढाका से करीब साढ़े तीन घंटे की दूरी पर है।

कौन था सम्राट मंडल

स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट द डेली स्टार को बताया कि सम्राट 'सम्राट वाहिनी' नाम के एक क्रिमिनल गैंग का लीडर था, जो जबरन वसूली और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल था।



सम्राट पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश छोड़कर भाग गया था और हाल ही में अपने गांव, कलिमोहर यूनियन के होसेंडांगा लौटा था।

कैसे हुई मौत

बुधवार रात करीब 11 बजे, वह और उसके गैंग के कुछ दूसरे सदस्य कथित तौर पर एक ग्रामीण, शाहिदुल इस्लाम के घर उससे पैसे वसूलने गए थे। परिवार के सदस्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गैंग के सदस्य लुटेरे हैं और दूसरे ग्रामीणों ने सम्राट को पकड़ लिया, जिसे पीट-पीटकर मार डाला गया, जबकि गैंग के ज़्यादातर दूसरे सदस्य भागने में कामयाब रहे।

पुलिस ने क्या बताया

असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पांगशा सर्कल) देब्रता सरकार ने बताया कि पुलिस ने सम्राट को भीड़ से बचाया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सरकार ने बताया कि सम्राट के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में कम से कम दो मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल था। सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को एक पिस्तौल और एक दूसरी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

पुणे के बुधवार पेठ में नकली मोबाइल एक्सेसरीज़ के खिलाफ बड़ा पुलिस एक्शन

संवाददाता |

पुणे, 25 दिसंबर 2025: बुधवार पेठ के तपकीर गल्ली में पुलिस ने नकली मोबाइल एक्सेसरीज़ बेचने वाले छह दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया और करीब ₹10,39,700 मूल्य का फर्जी माल जब्त किया।

कार्रवाई तब हुई जब एप्पल कंपनी के प्रतिनिधि विजय यशवंत सांगेलकर ने फरासरखाना थाने में शिकायत दी कि कुछ दुकानों में एप्पल ब्रांड के नकली चार्जर, इअरफोन, कवर्स और अन्य एक्सेसरीज़ को हूबहू मूल उत्पाद की तरह होलसेल व रिटेल में बेचा जा रहा है। पुलिस ने समर्थ प्लाज़ा और इड्रॉर्न बिज़नेस सेंटर के पास मौजूद कई दुकानों जैसे प्रेम टेलिकॉम, राज टेलिकॉम, ओम राजेश्वर शॉप आदि में छापा मारकर यह माल जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट कानून के उल्लंघन में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

Maharashtra | **NCP की गुप्त बैठक: शरद-अजित पवार गुटों में फिर सियासी होड़,**

NCP की गुप्त बैठक: शरद-अजित पवार गुटों में फिर सियासी होड़, पुणे-पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका चुनाव में सीट वितरण पर मंथन

मुंबई | आगामी 15 जनवरी 2026 को होने वाले पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव की सियासी रूपरेखा अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। राष्ट्रीयािस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों प्रमुख गुटों — शरद पवार और अजित पवार — के बीच पिंपरी-चिंचवड़ में एक गुप्त बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में रोहित पवार और एमपी डॉ. अमोल कोल्हे ने अजित पवार के साथ करीब एक घंटे तक बातचीत की। बताया जाता है कि यह बैठक दोनों गुटों के बीच मतभेदों को पाटा कर आगामी चुनाव में तालमेल बैठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि बातचीत के बाद



स्पष्ट घोषणा नहीं की गई, फिर भी सियासी गलियारों में दोनों पक्षों के बीच फिर से एकजुटता के संकेत मिल रहे हैं। राज्य स्तर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दो साल से शरद पवार और अजित पवार गुटों के विभाजन के बाद यह पहला बड़ा संवाद प्रयास है। यह बैठक न सिर्फ सीट शेयरिंग पर केंद्रित थी, बल्कि कांग्रेस और शिवसेना के साथ संभावित सहयोग पर भी

चर्चा के संकेत दिए गए।

पहली बैठक में शरद पवार गुट ने पुणे के लिए लगभग 40-45 सीटों की मांग रखी है, जबकि अजित पवार गुट वर्तमान में इससे कम संख्या पर ही सहमत दिख रहा है। अंतिम प्रस्ताव अगले दौर की बैठकों में तय होगा और उसके बाद ही न्याय संगत सीट बांटने का फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाएगा।

इस बीच, दोनों गुटों की संभावित एकजुटता से बीजेपी-शिंदे शिवसेना गठबंधन को चुनौती मिल सकती है, जो पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह बैठक इस चुनावी युद्ध की दिशा बदल सकती है और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष: राजनीतिक संतुलन और मतदाता धारणा को ध्यान में रखते हुए NCP के दो गुटों की यह बैठक महापालिका चुनाव 2026 के लिए बड़ा संकेत है। हालांकि फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे लेकर और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

छत्रपति संभाजीनगर में महापालिका चुनाव गठबंधन पर संकट, VBA का कांग्रेस सांसद पर आरोप



संवाददाता |

छत्रपति संभाजीनगर, 25 दिसंबर 2025 — आगामी महापालिका चुनावों को लेकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के बीच चल रही गठबंधन वार्ता में अड़चन सामने आई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला निरीक्षक योगेश बन ने कांग्रेस सांसद डॉ. कल्याण काले पर गठबंधन प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

योगेश बन के अनुसार, डॉ. काले VBA के साथ आघाड़ी बनाने को लेकर असमंजस में हैं, जिसके कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी पृष्ठभूमि में

VBA ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

वहीं सांसद डॉ. कल्याण काले ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तीनों दलों में समन्वय बना हुआ है और जल्द ही सीट बंटवारे पर सहमति बनेगी। कांग्रेस शहराध्यक्ष शेख युसुफ ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष ख्वाजा शरफोद्दीन ने 30 सीटों की मांग रखी है। उधर, VBA ने संकेत दिए हैं कि वार्ता विफल होने पर अन्य राजनीतिक विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में बिजली दरवाढ से उद्योजकों में गुस्सा, “वीज नियामक आयोग ने सार्वजनिक सुनावणी प्रक्रिया न अपनाई” उद्योजक बोले

अहिल्यानगर/मुंबई: महाराष्ट्र में बिजली के दर लगातार बढ़ने से छोटे, मध्यम और व्यावसायिक उद्योजकों में भारी नाराजगी पैदा हुई है। पिछले कुछ महीनों में बिजली देयकों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे उद्योजक अन्यायकारक और अत्यधिक मान रहे हैं। स्थानीय उद्योग संघ ‘आमी’ (Ahilyanagar Small & Medium Industries Association) के अध्यक्ष जयदत्त खाकाळ तथा महाराष्ट्र विद्युत कंत्राटदार संघटन के अध्यक्ष उमेश रेखे ने ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस से वीज दर वृद्धि को तत्काल रद्द करने का आग्रह किया है। वे मांग कर रहे हैं कि स्थापित सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लाभ भी पूर्ववत किए जाएं।

उद्योजकों का आरोप है कि वीज नियामक आयोग ने महावितरण की याचिका पर सार्वजनिक सुनावणी प्रक्रिया का पालन किए बिना दर वृद्धि आदेश जारी किया है, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त

बोझ पड़ा है। मार्च 2025 में जनसुनावणी के बाद जैसे ही महावितरण ने जून में पुनर्विलोकन के लिए याचिका डाली, आयोग ने सही प्रक्रिया न अपनाने हुए बिजली दरों में और वृद्धि कर दी। इससे औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आम जनता प्रभावित हो रहे हैं।

उद्योग संघों ने बिजली नियामक आयोग के खिलाफ आपत्तियाँ जमा करने, सुझाव देने और सार्वजनिक सुनावणी में भाग लेने का आवाहन किया है जो विविध शहरों में 2 से 8 जनवरी के बीच आयोजित होगी। उन्होंने सभी नागरिकों तथा उपभोक्ताओं से अपनी आवाज उठाने की अपील की है ताकि उचित पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जा सके। उद्योजकों का कहना है कि यदि बिजली दरवाढी को तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे उद्योगों की लागत बढ़ेगी और आर्थिक दबाव में वृद्धि होगी, जिसका असर आम ग्राहकों तक भी पहुँचेगा।



सरकारी बकाया भुगतान में देरी ने ठेकेदार को चोर बना दिया, यवतमाल में उपसरपंच गिरफ्तार

यवतमाल, 25 दिसंबर 2025 — शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का भुगतान समय पर न मिलने से कई ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में आर्णी मार्ग के पास एक चौकाने वाली घटना सामने आई, जहाँ कर्ज चुकाने के दबाव में एक उपसरपंच ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

आवधूतवाडी क्षेत्र की एक हार्डवेयर दुकान से गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे लगभग ₹9 लाख की नकदी चोरी हुई। दुकान संचालक साबीर हुसेन

भारमल के अनुसार, दुकान खोलने के लिए रखी गई रकम बैग में थी, तभी एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर बैग लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढका होने से पहचान मुश्किल रही।

पुलिस जांच में तळेगाव-भारी निवासी उपसरपंच दिनेश भाऊराव मंडाले (42) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पीड़ित को दूध सप्लाई करता था और भुगतान न मिलने से आर्थिक दबाव में था। पुलिस ने चोरी का बैग बरामद कर लिया है। आगे की जांच जारी है।



बीएमसी चुनाव 2026: ठाकरे-मनेस vs महायुती — मुंबई में कड़ा मुकाबला

मुंबई (विशेष रिपोर्ट): जनवरी 2026 में होने वाले बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पटल पर एक रोमांचक संघर्ष उभरकर आया है। शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की युति बनाम शिवसेना-भाजपा महायुती के बीच मुकाबला बेहद करीब बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को बराबरी का अवसर दिख रहा है।

लोकल विश्लेषकों और Vote Vibe India के आंकड़ों के अनुसार यदि

पुरानी वोटर रुझान की गणना बीएमसी चुनाव में लागू होती है, तो ठाकरे बंधुओं की युति (UBT-MNS) लगभग 90 से करीब सीटें जीत सकती है, वहीं महायुती गठबंधन को लगभग 91 सीटों तक सफलता मिल सकती है। इस तरह परिणाम एक रोमांचक और टक्कर-भरे मुकाबले की ओर संकेत कर रहे हैं।

मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 सीटों की आवश्यकता होगी। कोई भी बड़ा दल अकेले बहुमत

हासिल नहीं कर पाने की स्थिति में है, जिससे छोटे दल या गठबंधन किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी परिणाम न केवल पार्टियों की वर्तमान ताकत को परखेगा, बल्कि भविष्य में राज्य में राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे। जनता की पहली प्रतिक्रिया और मतदान पैटर्न के आधार पर अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन बीएमसी चुनाव 2026 मुंबई की राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ बन सकता है।

वोटर आईडी कार्ड में पता और नाम अपडेट कैसे करें: आसान ऑनलाइन प्रक्रिया



अगर आपका वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) पर पता बदलना या नाम में सुधार करना है, तो आप घर बैठे ही यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के **मुख्य आयुक्त दिनेश टी. वाघमारे ने दी है।

पता बदलने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर लॉगिन करें। यहाँ ‘Migration to another place’ या ‘Correction of Entries’ में जाकर Form-8 भरें और नया पता, जन्म-तिथि तथा पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें। पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

नाम सुधार की स्थिति में भी वही Form-8 चुना जाता है। इसमें आपको अपना गलत नाम/आडनाव बदलकर सही नाम दर्ज करना है और पहचान दस्तावेज़ जैसे आधार या जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना है। सबमिट करने के बाद सिस्टम द्वारा आवेदन पर वेरिफिकेशन होगी।

राज्य निवडणूक आयोग प्रमुख दिनेश वाघमारे ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल, समय-बचत वाली और वोट डालने के अधिकार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक बार आवेदन जमा हो जाने पर आप “Track Application Status” विकल्प से उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इस तरह से आपका वोटर आईडी नाम और पता दोनों अपडेट होकर आपको नए विवरण के साथ जारी किया जाएगा। याद रखें: चुनाव से पहले यह अपडेट करना बहुत जरूरी है ताकि मतदान में कोई परेशानी न हो।

IRCTC ने तात्काल टिकट बुकिंग में लागू किया नया OTP-आधारित प्रमाणीकरण नियम, यात्रियों के लिए पारदर्शी प्रणाली

मुंबई (विशेष रिपोर्ट):

भारतीय रेल और IRCTC ने तात्काल टिकट (Tatkal Ticket) आरक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है, जिससे टिकट बुकिंग और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। पश्चिम रेलवे के बयान के अनुसार अब मोबाइल OTP (वन-टाइम पासवर्ड) की सफल प्रमाणीकरण के बाद ही तात्काल टिकट जारी किया जाएगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य टिकट दुरुपयोग और दलालों द्वारा असामयिक आरक्षण को रोकना है।

नए नियम के तहत यह व्यवस्था IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप, पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंट बुकिंग सभी स्थानों पर लागू होगी। आरक्षण के समय

यात्रियों के दिये गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे सही तरीके से मान्य (verify) करना अनिवार्य होगा। तभी टिकट पुष्टि हो सकेगी।

यह सुधार पहले से लागू कई सुरक्षा कदमों का हिस्सा है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण भी शामिल है। इस आधार प्रमाणीकरण के कारण अब केवल वही यात्री तात्काल टिकट बुक कर सकते हैं जिनका आधार संख्या उनके IRCTC अकाउंट से जुड़ा हुआ है।

रेलवे द्वारा यह भी बताया गया है कि पहले चरण में यह प्रणाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में लागू कर दी गई है, जिनमें वांद्रे टर्मिनस से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।

यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षण से पहले अपने मोबाइल नंबर और आधार विवरण को अपडेट रखें ताकि OTP प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से टिकट बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगी, जिससे असली यात्रियों को तात्काल टिकट मिलने में आसानी होगी और टिकट दलालों के गलत इस्तेमाल पर नियंत्रण आएगा। यात्री इस नई व्यवस्था के बारे में पहले से जानकारी लेकर अपनी यात्रा योजनाओं को समय पर सुनिश्चित कर सकते हैं और OTP सत्यापन के लिए सही मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

